VISION IAS

www.visionias.in

VISION IAS
M N 05 SEP 2022 No. 3
RECEIVED

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1839)

Name of Candidate	Ishwar lal Gurjar.		
Medium Eng./Hindi	Hindi	Registration Number	1295818.
Center	Delhi	Date	5 sep, 2022

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
   इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न / भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

Plot No. 857, 1st Floor, Banda Bahadur Marg (Opp Punjab & Sindh Bank), Dr. Mukherjee Nagar Delhi- 110009

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

1839

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. An independent umbrella body that brings the various central investigative agencies under one roof holds the key to shoring up their credibility. Discuss. **(150 words) 10**

एक स्वतंत्र अम्ब्रेला निकाय जो विभिन्न केंद्रीय जांच एजेंसियों को एक छत के नीचे लाता हो, उनकी विश्वसनीयता को बढ़ाने की कुंजी है। विवेचना कीजिए।

प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ वाद (2006) में सर्वोच्च न्यायालय ने एक 'राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग' का गठन कर सभी केन्द्रीय जाँच एजेंसियों (IB, CBI) को इसके तहत लाने की बात कही थी।

(लाभ) → (i) समन्वय में वृद्धि होगी।

वर्तमान में NIA व CBI के क्षेत्राधिकार की स्पष्टता न होने से टकराव होता है।

(ii) केन्द्रीय जाँच एजेंसियों के प्रमुखों को एक ही निकाय के नीचे लाकर बेहतर कार्य संस्कृति का विकास संभव

1839
VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(iii) आसूचना साझाकरण, तकनीकी व अनुभवों का लाभ (परस्पर) आतंकवाद/अलगाववाद व राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों से बेहतर निपट पायेगी।

(iv) राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त जैसे- CBI पर राजनीति

(v) क्षमता निर्माण व संसाधनों के प्रयोग में बेहतरी होगी।

अतः एक स्वतंत्र अम्ब्रेला निकाय द्वारा स्वतंत्र केन्द्रीय जाँच एजेन्सी के लक्ष्यों को पाया जा सकेगा।

1839

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. Discuss the significance of the Doctrines of Pith and Substance and Colourable Legislation with respect to Centre-state relations in India. **(150 words) 10**

भारत में केंद्र-राज्य संबंधों के संदर्भ में तत्व एवं सार के सिद्धांत और छद्म (आभासी) विधायन के सिद्धांत के महत्व की विवेचना कीजिए।

भारत में 7 वी अनुसूची, अनुच्छेद-246 के तहत शक्तियों का बँटवारा (राज्य व केन्द्र) के मध्य किया गया है। इसके तहत तीन सूचियाँ ① केन्द्रीय सूची ② राज्य सूची और ③ समवर्ती सूची है।

भा केन्द्र-राज्य सम्बंध व आभासी विधायन

① केन्द्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ होने के कारण कई मुद्दों पर केन्द्रीय विधान को अधिक महत्व मिलता है

② समवर्ती सूची पर संघ सरकार

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

के अभिमत को अधिक महत्व
जैसे- तीन कृषि कानून

(3) तत्व एवं सार सिद्धान्त के तहत केन्द्र को मूल विधि के साथ कार्यपालिका द्वारा अधीनस्थ विधान के निर्माण की शक्ति है।

(4) राज्य व केन्द्र के मध्य शक्ति विभाजन का केन्द्र की ओर झुका होना।

अतः तत्व एवं सार के सिद्धान्त द्वारा राज्य-केन्द्र सम्बंध में सुधार सम्भव होगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. Do you agree with the view that there should be simultaneous elections to the Lok Sabha and the State Legislative Assemblies in India? Discuss with suitable arguments. **(150 words) 10**

क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि भारत में लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन एक साथ होने चाहिए? उपयुक्त तर्कों के साथ चर्चा कीजिए।

17 वीं लोकसभा के चुनाव में परोक्ष रूप से 50 हजार करोड़ का खर्चा हुआ; एंव राष्ट्र में हमेशा कहीं ने कहीं चुनाव चलत रहने के कारण 'वन नेशन वन इलेक्शन' की माँग बढ़ी है।

लाभ
- विकास कार्यों में बाधा नहीं। उदा. आचार संहिता के कारण
- चुनावी खर्च व मशीनरी का दुरुपयोग नहीं।
- हर समय 'चुनावी मुड' की बजाए एक साथ चुनाव से जनता बेहतर निर्णय लेगी

1839
VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

⊛ प्रशासनिक दक्षता व प्रभावी चुनाव क्रियान्वयन के लिए जरूरी।

⊛ विधि आयोग व दिनेश गोस्वामी कमेटी ने निरन्तर चुनावों को अकुशल बताया।

चुनौतियाँ – ① एक साथ चुनाव के लिए कई विधानसभाओं को समय पूर्व समाप्त करना पड़ेगा → राजनीतिक विवाद बढ़ेगा।

② संविधान संशोधन जैसे की बाध्यता

③ सत्ता पक्ष (केन्द्र) को फायदा होगा।

④ चुनाव आयोग के पास संसाधनों की कमी होगी।

अतः एक साथ के बजाय दो या तीन स्लॉट में रखने पर विचार करना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. Discuss the need for codification of parliamentary privileges in India, in light of the uncertainty and ambiguity around them. (150 words) 10
भारत में संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में अनिश्चितता और अस्पष्टता के आलोक में, उनके संहिताकरण की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।

अनुच्छेद -105 के तहत संसदीय विशेषाधिकार प्रदान किए गए है।

(1) व्यक्तिगत विशेषाधिकार
- सांसदों को निर्बाध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (सदन में)
- सांसदों को 40 दिन सत्र के पूर्व व बाद आपराधिक संरक्षण

(2) सामूहिक विशेषाधि
- अपनी कार्यवाही के प्रकाशन को रोकने की
- गोपनीय बैठक की शक्ति
- अवमानना पर दण्ड की शक्ति

संहिताकरण की आवश्यकता

→ (i) विशेषाधिकारों की अस्पष्ट प्रकृति के कारण दुरुपयोग होता है। उदा० राज्यसभा के 12 सांसदों का निलम्बन

(ii) यह अनिश्चित है अतः सदन के अध्यक्ष द्वारा मनमर्जी व पक्षपाती व्याख्या की सम्भावना है।

(iii) यह सार्वजनिक अधिकारों व सूचना के अधिकार को सीमित करता है।

(iv) सांसदों का दुर्व्यवहार, अमर्यादित आचरण से विवाद

चुनौतियाँ → संहिताकरण करने से यह कानूनी रूप लेगा, जिससे न्यायिक समीक्षा के तहत मुकदमेबाजी बढ़ेगी। संहिताकरण से संसद की शक्तियाँ सीमित होगी।

अतः विशेषाधिकारों के लिए संसद को उच्च नैतिक संसदीय परम्पराओं को प्रतिमान बनाना चाहिए।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. While the Civil Services Board can be a step forward in making the Indian bureaucracy more effective, it has its own issues which need to be addressed. Analyse. **(150 words) 10**

हालांकि, सिविल सेवा बोर्ड भारतीय नौकरशाही को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक अग्रणी कदम हो सकता है, लेकिन इसके अपने मुद्दे हैं जिन्हें हल करने की आवश्यकता है। विश्लेषण कीजिए।

'सिविल सेवा बोर्ड' के गठन से भारतीय सिविल सेवा को एक मार्गदर्शक नेतृत्व प्रदान होगा। जिसकी जरूरत समय की मांग है।

(लाभ) (i) सिविल सेवा की यथास्थितिवादी औपनिवेशिक मानसिकता को तोड़ना

(ii) सामान्यज्ञ - विशेषज्ञ विवाद को रोकना

(iii) राजनेता - सिविल सेवक विवाद को कम करना → बेहतर समन्वय

(iv) सिविल सेवा में मिशन कर्मयोगी के सुधारों को लागू करने में प्रभावी।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

मुद्दे → (i) नौकरशाही को केन्द्रीकरण करने से रचनात्मकता कम होगी

(ii) सिविल सेवकों पर एक ओर राजनीतिक कार्यपालिका का नियंत्रण होगा तो दूसरी ओर सिविल सेवा बोर्ड की अपेक्षाएँ।

अतः सिविल सेवा बोर्ड का गठन सिविल सेवा को नया मार्गदर्शन व टीम इंडिया की भावना दे सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. Highlight the potential of India Digital Ecosystem Architecture (IndEA) 2.0 in transforming the ecosystem of service delivery in India. **(150 words) 10**
भारत में सेवा वितरण के पारितंत्र को रूपांतरित करने में इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम आर्किटेक्चर (IndEA) 2.0 की क्षमता पर प्रकाश डालिए।

इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम आर्कि-टेक्चर (IndEA 2.0) द्वारा ई-गवर्नेंस को अगले कदम तक पहुँचाया जा सकता है।

सेवा वितरण के परितंत्र में मदद

(क) Government to citizen की कनेक्टिविटी को बढ़ायेगा उदा- शिकायत निवारण तंत्र, फीडबैक को बेहतर करेगा।

(ख) सेवा तक बेहतर होगी

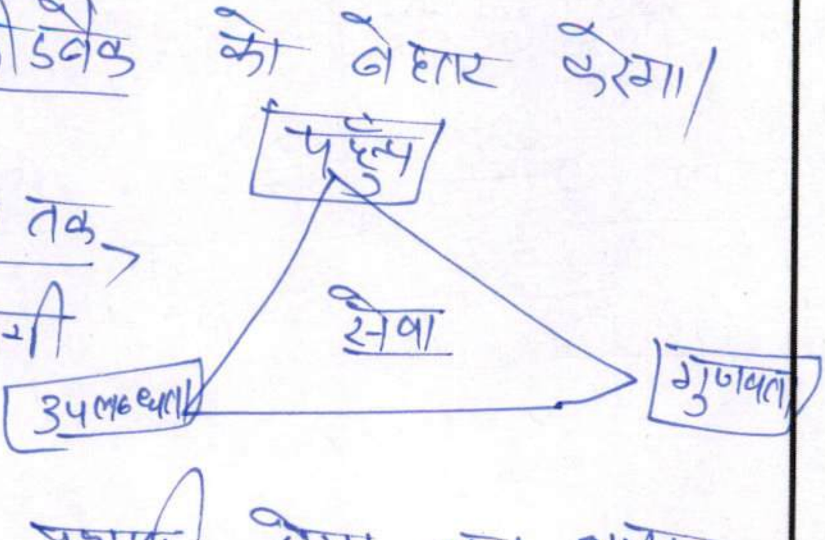

(ग) लागत प्रभावी होगा तथा शासन

में पारदर्शिता, जवाबदेहिता को बढ़ावा देगा।

(घ) ई-शासन → गुड गवर्नेंस के लक्ष्य को पाने में मदद गार होगा।

(ङ.) डिस्टेंस लर्निंग, टेलीमेडिसन, डिजी-लॉकर, ई-ऑफिस, ई-डिस्ट्रिक्ट को अधिक प्रभावी करेगा।

अतः NeGA 2.0 द्वारा भारत गवर्नेंस के अपने लक्ष्य मिनिमम गवर्नेंस गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस को पा सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. What is Civil Registration System? Highlight its importance and discuss the measures taken by the government to bring about improvements in it. (150 words) 10

नागरिक पंजीकरण प्रणाली क्या है? इसके महत्व पर प्रकाश डालिए और इसमें सुधार करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों पर चर्चा कीजिए।

'नागरिक पंजीकरण प्रणाली' के तहत नागरिक स्वयं अपना पंजीकरण ऑनलाइन कर सकता है तथा अपनी -पयनात्मक सूचना सरकार से साझा कर सकता है; यह एक राष्ट्रीय पहल है जहाँ नागरिक स्वंय अपना पंजीकरण/गणना करता है।

महत्व
(i) एक केन्द्रीकृत नागरिक आधारित डेटाबेस तैयार होगा।
(ii) सरकार द्वारा नीति-निर्माण में इस डेटा का बेहतर उपयोग होगा
(iii) नागरिकों के चिह्नीकरण व उनके

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

स्थिति द्वारा अवैध प्रवासन, पलायन का डेटा एकीकृत हो सकेगा।

(iv) इसके द्वारा फेक वोटर, फेक लाभार्थी की पहचान होगी।

(v) लाभार्थियों के दोहराव कम होगा।

उपाय
(i) इसका आधार से लिंक किया गया है।
(ii) ऑनलाइन वेबसाइट/पोर्टल के द्वारा।
(iii) स्व प्रमाणित डेटा को साझा करना

अतः नागरिक पंजीकरण द्वारा सरकार लोक नीति निर्माण, क्रियान्वयन मूल्यांकन को बेहतर किया जा सकेगा।

8. The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and Their Rehabilitation Act, 2013, provides an effective mechanism for empowerment of the intended beneficiaries in the society. Critically discuss. **(150 words) 10**

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 समाज में इच्छित लाभार्थियों के सशक्तीकरण के लिए एक प्रभावी तंत्र प्रदान करता है। समालोचनात्मक चर्चा कीजिए।

हाथ से मैला उठाने की अमानवीय प्रथा को समाप्त करने के लिए लाए गए इस एक्ट द्वारा सफाई कर्मियों के जीवन, पुर्नवास में सुधार के प्रयास हेतु एक 'राष्ट्रीय सफाई कर्मी परिषद' का गठन किया गया।

लाभ
- हाथ से मैला उठाने को प्रतिबेधित किया
- इसे एक दण्डनीय कार्य बनाया
- मैला उठाने वालों के पुर्नवास हेतु वित्तीय सहायता की गई।
- सामाजिक सुरक्षा (बीमा, पेंशन) शिक्षा

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- राज्य स्तर पर समितियों का गठन
- भेदभाव के खिलाफ आपराधिक दण्ड

चुनौतियाँ – (i) क्रियान्वयन सम्बंधी बाधाएँ
(ii) अभी भी सफाई कर्मियों के पास उपकरणों व संसाधनों का अभाव है।
(iii) मैला ढोने की प्रथा को जाति व्यवस्था द्वारा पोषण।

आगे की राह – सरकार ने परिषद की अवधि को और बढ़ा दिया है तथा निगरानी को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. Discuss the reforms that must be undertaken to strengthen the World Trade Organisation in order to address the vulnerabilities in the present global trading system. **(150 words) 10**

वर्तमान वैश्विक व्यापार प्रणाली में विद्यमान कमियों को दूर करने के लिए विश्व व्यापार संगठन को सुदृढ़ करने हेतु उस पर किए जाने वाले सुधारों की विवेचना कीजिए।

GATTS 1 जनवरी 1995 में WTO की स्थापना। वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने व निष्पक्ष, समान वैश्विक व्यापार प्रणाली के विकास हेतु हुआ। मुख्यालय - जिनेवा

वैश्विक व्यापार प्रणाली की कमियाँ

1. बढ़ता हुआ संरक्षणवाद
   उदा० अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी
2. विकासशील देशों का मुद्दा
3. ट्रेड वॉर करेंसी वॉर
4. खाद्य सुरक्षा
5. विकसित देशों द्वारा निर्यात पर रोक
   उदा० भारत के खिलाफ सेनेटरी प्रतिबंध
6. कृषि सब्सिडी का लंबित मुद्दा
7. डम्पिंग का मुद्दा
8. तकनीकी असमानता

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

सुधार — (A) WTO पर विकसित देशों का अधिक प्रभाव है। जिसे कम करने के लिए विकासशील देशों द्वारा AoA व GATS में सुधार करना

(B) WTO में विवाद निवारण तंत्र में सुधार करने व अपीलीय प्राधिकरण में जजों की नियुक्ति करना।

(C) WTO की मंत्रिस्तरीय बैठक को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सर्वसहमति के निर्णय को बाध्यकारी बनाना

(D) संरक्षणवाद व वि-वैश्वीकरण को रोकना।

अतः WTO की प्रांसगिकता बनाए रखने के लिए व्यापक सुधारों की जरूरत है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. State the significance of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Also, discuss the need for a legally binding Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction (BBNJ) agreement.

(150 words) 10

संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS) के महत्व का उल्लेख कीजिए। साथ ही, कानूनी रूप से बाध्यकारी राष्ट्रीय अधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता (BBNJ) समझौते की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।

'UNCLOS' समुद्री सीमाओं व क्षेत्रों के लिए वैश्विक कानून है जो राष्ट्र के प्रभाव क्षेत्र का निर्धारण करता है जैसे - (i) प्रादेशिक क्षेत्र (ii) अनन्य आर्थिक क्षेत्र आदि के रूप में

महत्व - (i) नियम आधारित मुक्त नौवहन के लिए UNCLOS जरूरी है।

(ii) कॉमन रिसोर्सेज (अनन्य सागर -200 समुद्री मील) की सुरक्षा हेतु जरूरी।

(iii) डीप ओशन संसाधनों के वितरण हेतु जरूरी है।

(f) समुद्री संचार मार्ग की मुक्त व स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है।

BBNJ की आवश्यकता

(क) जलीय पारितंत्र की रक्षा हेतु जैसे- प्रवाल भित्तियों का संरक्षण

(ख) मत्स्यपालन क्षेत्र की धारणीयता हेतु अत्यन्त आवश्यक

(ग) ब्लू इकोनोमी के लिए आवश्यक

(ङ) मेगा बायो डाइवर्सिटी के संरक्षण हेतु

अतः UNCLOS व BBNJ समझौते द्वारा SDG-13 (life in the water) को साधा जा सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. Critically assess the role played by the National Human Rights Commission as a watchdog of human rights violations in India. **(250 words) 15**
भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन के प्रहरी के रूप में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा निभाई गई भूमिका का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

मानवाधिकार आयोग की

स्थापना वर्ष - 1992 में सांविधिक संस्था के रूप में मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु की गई है। इसे CrPC -1908 के तहत एक दिवानी न्यायालय के अधिकार प्राप्त है।

भूमिका -(A) मानवाधिकारों के उल्लंघन के प्रहरी के रूप में

└ जैसे - विचाराधीन कैदियों की रिहाई
- मैला उठाने वाले के अधिकार
- बाल श्रमिकों के अधिकार

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(B) जागरूकता व प्रोत्साहन के रूप

↳ मानवाधिकार दिवस पर कार्यक्रम

- NGO को पुरस्कार व सहयोग

(1) मानवाधिकारों पर अनुसंधान व वैश्विक UNHRC के तहत भारत का प्रतिनिधित्व करने के रूप में।

(2) कारागार व कैदियों के जीवन में सुधार हेतु, जेलों का निरीक्षण करना।

(3) पीड़ितों को मुआवजा व प्रोत्साहन देने के रूप में

(v) जातीय, लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध

चुनौतियाँ (i) यह दंतहीन संस्था है।

यह न तो अपराधी को सजा दे सकती है न ही पीड़ित को मुआवजा

(ii) इसकी प्रकृति सलाहकारी है।

(iii) अधिकांश मामलों में सरकार व प्रशासन सिफारिशों को नजरअंदाज

(iv) जाँच अधिकरण सहायता नहीं करता।

(v) रिपोर्ट पर संसद में चर्चा नहीं होती।

अतः मानवाधिकार आयोग के कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए इसके सशक्तिकरण की आवश्यकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. Discuss how the integration of information and communications technology (ICT) in the dispute resolution processes will help in overcoming the challenges associated with the functioning of courts and Alternative Dispute Resolution (ADR) forums. **(250 words) 15**

विवेचना कीजिए कि विवाद समाधान प्रक्रियाओं में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का एकीकरण अदालतों एवं वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) मंचों के कामकाज से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने में किस प्रकार सहायता करेगा।

हाल ही में गुजरात हाइकोर्ट ने ICT का प्रयोग करते हुए मुकदमों को ट्रैक करने के लिए डिजिटल डैशबोर्ड 'जस्टिस क्लॉक' की पहल की है।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का विवाद समाधान व ADR में प्रयोग के लाभ-

(i) न्यायिक प्रक्रिया में 4.7 करोड़ केस लम्बित है। ICT द्वारा लम्बित मुकदमों की सुनवाई को व्यवस्थित व त्वरित किया जा सकता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(ii) पूर्व CJI ने विशिष्ट विवादों में AI एल्गोरिद्म के प्रयोग की सलाह दी जैसे - इन्श्योरेंस क्लेम के केस

(iii) ADR के रूप में मध्यस्था के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म व पोर्टल बनाना।

(iv) लोक अदालतों के विवादों में कम्प्यूटर, AI, डेटा एनालिटिक्स, ऑनलाइन सुनवाई द्वारा प्रभावी निस्तारण।

(v) ई-कोर्ट व नेशनल न्यायिक डेटा ग्रीड' द्वारा PIL फाइलिंग को आसान

(vi) वर्तमान में लाइव स्ट्रीमिंग द्वारा पारदर्शिता का प्रयास किया जा रहा है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

चुनौतियाँ -> (i) ICT उपकरणों व इंटरनेट कनेक्टिविटी का अभाव है।

(ii) न्यायिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण का अभाव है, कौशल व दक्षता की कमी

(iii) संवेदनशील डेटा व गोपनीयता का मुद्दा।

(iv) साइबर सिक्योरिटी व भौतिक सुनवाई की बाध्यता का मुद्दा।

आगे की राह - ICT द्वारा न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावी व तीव्र किया जा सकता है अतः इस हेतु ICT अवसंरचना का विकास, प्रशिक्षण, NALSA द्वारा जागरूकता की जरूरत है।

13. Despite various provisions concerning disqualification of legislators under The Representation of The People Act, 1951, the issue of criminalization of politics is still unresolved to a large extent in India. Discuss.

(250 words) 15

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत विधायकों की निरर्हता से संबंधित विभिन्न प्रावधानों के बावजूद, भारत में राजनीति के अपराधीकरण का मुद्दा अभी भी काफी हद तक अनसुलझा है। विवेचना कीजिए।

~~लोक प्रति~~ 17वी लोक सभा में 43% सांसदो पर आपराधिक मुकदमे दर्ज है, जो 16वी लोकसभा मे 26% ही था, अर्थात राजनीति में अपराधीकरण में बढोतरी हुई है।

(प्रावधान) - (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-8 व लिलि थोमस वाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार 2वर्ष से अधिक जेल की सजा काने वाले व्यक्ति को आगामी 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

निरर्थक माना जाता है।

सुब्रमण्यम स्वामी केस व लोक प्रहरी वाद में भी सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रतिनिधियों पर लगाम लगाने के निर्देश दिए है।

कारण — (i) राजनीतिक व अपराधिक जगत का गठजोड़, राजनीति का पहले अपराधीकरण हुआ अब अपराधी का ही राजनीतिकरण हो गया।
उदा० लॉ ब्रेकर ही लॉ मेकर बने।

(ii) धीमी न्यायिक प्रक्रिया व बाहुबल, धन बल का बढ़ता प्रयोग

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(iii) राजनीति में अपराधीकरण का महिमामंडन करने की प्रवृत्ति

(iv) राजनीतिक दल जीताऊ उम्मीदवार को टिकट देता है न कि ईमानदार को

(v) जनता में व्यक्तिपूजा की भावना, राजनीतिक साक्षरता का अभाव।

उपाय - (A) आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को टिकट न दिया जाए।

(B) उम्मीदवार की पृष्ठभूमि को अखबारों में प्रकाशित करना।

(c) लोक प्रतिनिधित्व एक्ट को मजबूत कर निर्वाचन आयोग को सशक्त करना।

अतः दिनेश गोस्वामी रिपोर्ट कि सिफारिशों को लागू कर राजनेता अपराधी के नेक्सस को तोड़ा जाए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. It is time for reforms, which recognise that urban local bodies (ULBs) need permanent, buoyant revenue sources to match the growing demands of an increasing urban population. Discuss. **(250 words) 15**

यह सुधारों का समय है जो यह पहचान करता है कि शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को बढ़ती शहरी आबादी की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए स्थायी, वृद्धिशील राजस्व स्रोतों की आवश्यकता है। विवेचना कीजिए।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार भारत की शहरी आबादी = 34% है जो 2030 तक 40% तक बढ़ जायेगी, बढ़ता शहरीकरण शहरी स्थानीय निकायों के समक्ष संसाधनों का दबाव व वित्त की कमी जैसी चुनौतियां खड़ी करता है

वर्तमान स्थिति व चुनौतियां

→ (i) शहरी स्थानीय निकाय की कुल राजस्व आय GDP का मात्र 1% है जो अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के 6-7% से कम है।

(ii) शहरी निकाय के अपने वित्त स्रोतों

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

के लिए राज्य व केन्द्रीय वित्त हस्तांतरण पर निर्भर है; कुल वित्त का 96% हस्तांतरण द्वारा

(iii) शहरी निकायों के स्वंय के स्रोतों से आय मात्र - 6% है जो ब्राजिल, जर्मनी में 40% है।

(iv) GST के कारण मनोरंजन, कर व विज्ञापन कर भी प्राप्त नहीं होता।

(v) राज्य वित्त आयोग का गठन समय पर नहीं होता जैसे - मेघालय में 3rd

उछालशील राजस्व स्रोतों की आवश्यकता

(i) पेयजल, स्वच्छता, विद्युत माँग, ठोस अपशिष्ट के बढ़ता कार्य के कारण

(ii) बढ़ता शहरीकरण से संसाधनों की माँग में भी बढ़ोतरी हुई।

(iii) जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु।

(iv) समावेशी शहरीकरण शहरी गरीबी को बढ़ने के लिए - मलिन बस्ति

(v) स्मार्ट सिटी के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु।

आगे की राह, (1) स्मार्ट सिटी का विस्तार

100 शहरों की बजाय अधिक संख्या में

(2) स्वयं के वित्त स्रोत को बढ़ावा देना

उदा० - शुल्क, Tax लगाने की छूट

(3) 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों को

लागू करना, अनुदान बढ़ाना।

(4) राज्य के राजस्व पूल में हिस्सा बढ़ाना

अतः शहरी स्वच्छता मिशन,

जल जीवन मिशन, आवास मिशन, स्वर्ण मिशन

का क्रियान्वयन करते हुए वित्तीय रूप

से सशक्तिकरण करना होगा (Smart)

15. The role of the civil society organisations (CSOs) in India is changing in contemporary times and has become increasingly more complex. Discuss.
(250 words) 15

समकालीन समय में भारत में नागरिक समाज संगठनों (CSOs) की भूमिका बदल रही है और निरंतर अधिक जटिल होती जा रही है। चर्चा कीजिए।

नागरिक समाज संगठन से तात्पर्य उस व्यापक नागरिक समाज से है जिसमे NGO, SHG, गैर-राज्य संगठन, दबाव व हित समूह शामिल होते है।

नागरिक समाज संगठन : बदलती भूमिका

→ (क) सरकार के पूरक के रूप में यह संगठन सेवा वितरण, जनकल्याण के कार्यों में सहयोग कर रहे है।
जैसे – → स्माइल फाउंडेशन द्वारा 4 लाख बच्चों की घर वापसी
(ख) प्रशासन से जवाबदेही व पारदर्शिता

की माँग करने व सुधार की कार्यवाही।

उदा० – RTI एक्ट के लिए आन्दोलन
लोकपाल अधि० हेतु आन्दोलन

(ग) सरकार से नए नागरिक अधिकारों की माँग व रक्षा

उदा० जनसुनवाई का अधिकार
सूचना का अधिकार

(घ) पर्यावरण संरक्षण व समावेशी विकास हेतु कार्य जैसे – चिपको आन्दोलन
नर्मदा बचाओ आन्दो०

(ङ) मानव कल्याण हेतु कार्य, सेवा वितरण में सहयोग जैसे – CRY NGO

(च) प्रशासन को सहयोग →

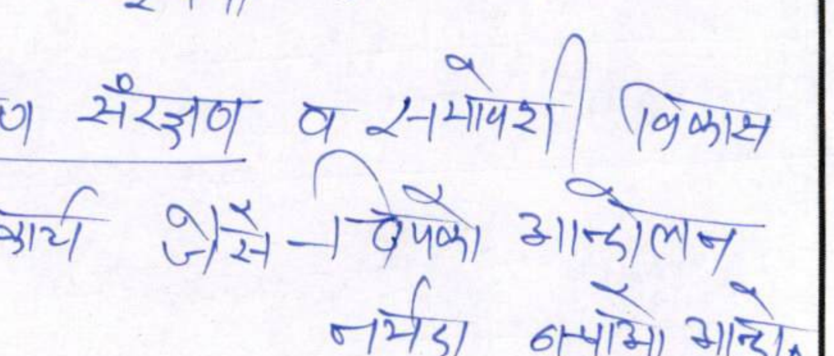

1839
VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

बदलाव के कारण → (i) जनकल्याणकारी राज्य की बढ़ती माँगें

(ii) राज्य व शासन में बढ़ती जनसहभागिता व समावेशी दृष्टिकोण

(iii) सूचना अधिकार → जागरूकता बढ़ी → सक्रियता बढ़ी

(iv) डिजिटल साक्षरता, तकनीकी दक्षता के कारण सहयोग।

जटिल होती भूमिका : चुनौतियाँ

* प्रशासन से बढ़ता टकराव
* विकास कार्यों में बाधा
* विदेशी फंडिंग का मुद्दा
* अति सक्रियता
* नीतिगत विकलांगता

अतः नागरिक समाज सरकार के सहयोगी व पहरेदार के रूप में काम करता है जो शासन को अधिक जनमित्र बनाता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. Though the Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) aims to address the inequity in development in India, there are a number of issues which plague the scheme. Discuss. **(250 words) 15**
हालांकि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) का उद्देश्य भारत में विकास में असमता से निपटना है, लेकिन ऐसे कई मुद्दे हैं जो इस योजना को प्रभावित करते हैं। विवेचना कीजिए।

'MPLAD' योजना के तहत प्रत्येक सांसद को '5 करोड़' के विकास फंड प्रदान होता है, जो अव्यपगत राशि होती है, इसका प्रयोग लोकसभा सांसद अपने क्षेत्र व राज्यसभा सांसद संबंधित राज्य में अवसंरचना (पेयजल, स्वच्छता) हेतु कर सकता है।

उद्देश्य → (i) सांसदों के माध्यम से अवसंरचनात्मक असमानता जैसे- अस्पताल, स्कूल पेयजल के अभाव को पूरा करना है।

(ii) इसका 20% हिस्सा अनुसूचित जाति, जनजाति क्षेत्र के विकास हेतु प्रयुक्त किया जाता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(iii) योजना का क्रियान्वयन जिला प्रशासन द्वारा सांसद के अनुमोदन से किया जाता है।

(iv) ग्रामीण अवसंरचना का विकास करना।

मुद्दे —(i) वर्ष 2020-21 में दो वर्ष के लिए इसे स्थगित करने से विकास कार्यों में देरी हुई।

(ii) स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों में भेदभाव व भ्रष्टाचार का मुद्दा जैसे- सांसद द्वारा कमीशन लेना।

(iii) कई सांसदों द्वारा अपनी राशि का प्रयोग ही नहीं किया।

(iv अनुपालन की जटिल प्रक्रिया के कारण, कम प्रभावी है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

आगे की राह - (A) कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MOSPI) द्वारा इस योजना के विकास कार्यों को ट्रैक करने हेतु एकीकृत डेटा ग्रिड व वेबसाइट का निर्माण करना।

(B) जिला प्रशासन द्वारा निष्पित कार्यों के निरीक्षण रिपोर्ट को सार्वजनिक करना।

(C) स्थानीय संस्थाओं व लोकल गवर्नेंस (ग्राम पंचायत, नगरपालिका) द्वारा योजना बनाना।

अतः संसद सदस्य स्थानीय विकास योजना द्वारा विकास कार्यों की स्थानीय आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए।

17. Highlighting the factors responsible for the growth of EdTech sector in India in recent times, discuss its benefits. Also, state the concerns associated with it. **(250 words) 15**

हाल के दिनों में भारत में एडटेक क्षेत्रक के विकास के लिए उत्तरदायी कारकों पर प्रकाश डालते हुए, इसके लाभों पर चर्चा कीजिए। साथ ही, इससे जुड़ी चिंताओं का भी उल्लेख कीजिए।

वर्ष २०२४ के दौरान भारत में यूनिकॉर्न की कुल संख्या - 81 थी जिसमे IT सेक्टर के बाद एडटेक कंपनियाँ प्रमुख थी जैसे- बाइजूस & अनएकेडमी

उत्तरदायी कारक

(क) डिजिटल कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी

← इंटरनेट पहुँच बढ़ी

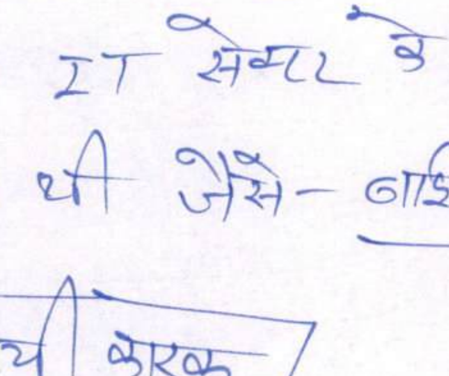

(ख) भारत में डिजिटल इंडिया, डिजिटल साक्षरता, ने ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को एक दशक में 10 गुना बढ़ाया है

(ग) भारत का उभरता बाजार व निवेशकों की बढ़ती रूचि। भारत में वर्तमान में 65 करोड़ इन्टरनेट यूजर है जो 2025 तक 85 करोड़ तक पहुँच सकते है। विदेशी निवेशक (FDI) जैसे जिओ रिलायंस में फेसबुक का निवेश

(घ) Covid-19 महामारी ने परम्परागत शिक्षा की जगह ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया। 'असर' की रिपोर्ट के अनुसार महामारी के दौरान भारत में पढ़ाई हेतु 25% परिवारों ने स्मार्ट फोन खरीदा।

(लाभ) → (i) शिक्षा की पहुँच दूर तक हुई
(ii) डिस्टेंस लर्निंग बढ़ी।

(iii) लर्निंग पॉवर्टी व लर्निंग गैप कम होगा

(iv) गुणवत्ता व वहनीयता बढ़ी

(v) स्मार्ट क्लास, प्रौद्योगिकी द्वारा सीखना प्रभावी हुआ।

(vi) शिक्षा की उपलब्धता (↑) –

चुनौतियाँ – (i) लर्निंग असमानता बढ़ेगी
जैसे – गरीब – अमीर
गाँव – शहर

(ii) डिजिटल डिवाइड ASO मात्र 27% ग्रामीण परिवारों के पास इन्टरनेट है।

(iii) तकनीकी असमानता ASO 15% ग्रामीण परिवारों के पास कम्प्यूटर है।

(iv) स्कूली शिक्षा, शारीरिक शिक्षा का अभाव → अवसाद → अकेलापन (↑)

अतः एडटेक ओरा को पूरक रूप में लेना चाहिए तथा इसके विनियमन के प्रयास भी किए जाए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. Bring out the role of Accredited Social Health Activist (ASHA) workers in delivering health services in rural India. Also, suggest the measures that can be taken to overcome the challenges faced by them. **(250 words) 15**

ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) की भूमिका पर प्रकाश डालिए। साथ ही, उनके द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को दूर करने के उपाय भी सुझाइए।

कोविड-19 महामारी के दौरान आशा सहयोगिनी की भूमिका लोगों को टीकाकरण हेतु जागरूक करने व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सहयोग करने के रूप में रही।

आशा: भूमिका

(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सहयोग जैसे- टीकाकरण, जागरूकता, होम आइसोलेशन, संस्थागत प्रसव, बाल स्वास्थ्य में इनकी बहुआयामी भूमिका है।

(ii) एकीकृत बाल विकास सेवाओं (ICDS) में पोषण वितरण व स्वास्थ्य

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

मानकों की पूर्ति में सहयोग।

(iii) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ग्रामीण डॉक्टर के सहायक के रूप में सहयोग

(iv) महिला स्वास्थ्य व पोषण की योजनाओं

→ जननी शिशु सुरक्षा योजना
→ प्रधानमंत्री मातृ वंदन स्कीम
→ सुपोषण माँ योजना
→ निःशुल्क सैनेटरी नैपकिन वितरण

में सामुदायिक सहयोग व स्थानीय लोगों के संवाद हेतु।

(चुनौतियाँ) — (i) न्यूनतम वेतन की चुनौती

विभिन्न राज्यों में 3000 से 6000 के मध्य वेतन, जो मनरेगा मजदूर से भी कम है, इसलिए आशा के सशक्तिकरण की जरूरत है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(ii) संसाधन अभाव - आशा के पास, मोबाइल, इंटरनेट कनेक्टिविटी, परिवहन साधनों का अभाव है।

(iii) प्रशिक्षण व जानकारी का अभाव है

(iv) पितृसतात्मक मानसिकता के कारण आशा के प्रति
- अस्वीकृति भाव
- (covid-19 दौरान हमले/हिंसा

आगे की राह -(A) न्यूनतम पारिश्रमिक का एक सार्वभौमिक मॉडल तैयार

(B) आशा को स्किल → रीस्किल व प्रशिक्षण

(C) आवधिक प्रोत्साहन, लक्षित एक्शन प्लान द्वारा प्रोत्साहित करना।

(D) आंगनवाड़ी व्यवस्था व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ड्यूटियों/कार्यों के लिए दिशा-निर्देशों का सेट तैयार करना।

अतः आशा सशक्तिकरण द्वारा SDG-3 व 5 की पूर्ति सम्भव होगी।

19. Discuss the various concerns that have arisen for India after the Taliban takeover of Afghanistan. Also, suggest the measures that India should take in the given context. **(250 words) 15**

तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर अधिकार करने के बाद भारत के लिए उत्पन्न विभिन्न चिंताओं की विवेचना कीजिए। साथ ही, उन उपायों का सुझाव दीजिए जो इस संदर्भ में भारत द्वारा अपनाए जाने चाहिए।

अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान पर अधिकार कर लिया, भारत ने तालिबानी प्रशासन को औपचारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन हाल में कांधार में अपना दूतावास खोला है।

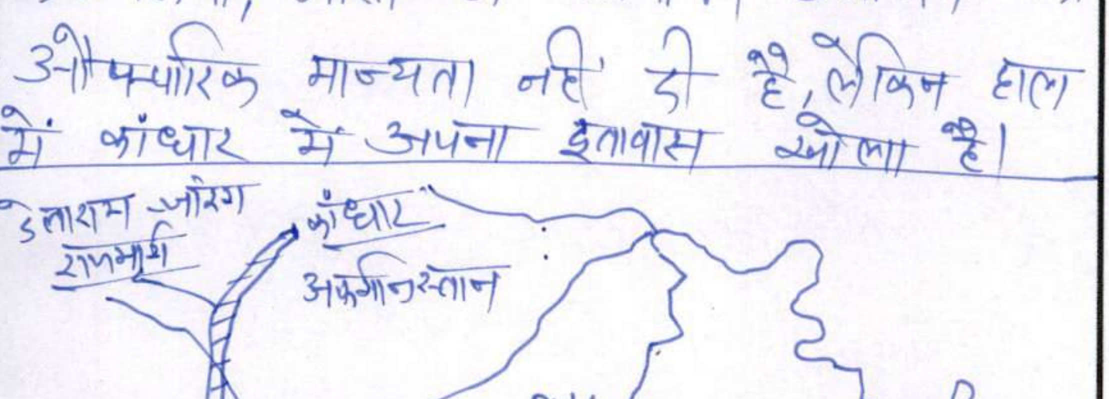

भारत की चिंताएं — (1) तालिबान के आगमन से जैश-ए-मुहम्मद, अलकायदा, हक्कानी जैसे आतंकवादी कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ा सकते है, जो भारत की सुरक्षा को खतरा है।

(2) भारत ने अफगानिस्तान के निर्माण व अवसंरचना में 3 बिलियन डॉलर का निवेश किया जो अनिश्चितता व निष्क्रिय हो सकता है।

(3) भारत ने सलमा बांध, अफगानिस्तान का संसद भवन, डेलाराम-जरांग राजमार्ग व स्कूल, हॉस्पिटल आदि का निर्माण कार्य किया, तालिबान के कारण इनका लाभ भारत को नहीं मिलेगा।

(4) तालिबान की पाकिस्तान व चीन से बढ़ती निकटता भारत के लिए सामरिक चुनौती है।

(5) अफगानिस्तान मध्य एशिया का प्रवेश द्वार है अतः भारत की 'कनेक्ट सेन्ट्रल एशिया' पॉलिसी निष्प्रभावी हो सकती।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(6) अफगानिस्तान में अस्थिरता भारत के रक्षा, सामरिक, आर्थिक हितों के खिलाफ

उपाय → * अफगानिस्तान में आए भूकम्प में भारत ने मानवीय सहायता भेजकर सद्भावना हासिल की

* तालिबान से बैक चैनल वार्ता आरम्भ करना ताकि पाकिस्तान की बढ़त को रोका जा सके।

* SCO के सुरक्षा सलाहकारों की दिल्ली घोषणा को लागू करना होगा।

* पीपुल टू पीपुल कॉन्टैक्ट का सॉफ्ट पॉवर (क्रिकेट, बॉलिवुड) द्वारा बनाए रखना

अतः एक स्थिर अफगानिस्तान के लिए भारत को बहुपक्षीय सहयोग व संवाद द्वारा सक्रिय प्रयास करना। गुजराल सिद्धान्त के अनुसार

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. Bangladesh is not only a key part of India's "Neighbourhood First policy" but also crucial for the "Act East policy". In this context, discuss the steps taken by the two countries to strengthen their relationship.

(250 words) 15

बांग्लादेश न केवल भारत की "नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी" का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि "एक्ट ईस्ट पॉलिसी" के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में, दोनों देशों द्वारा अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों की विवेचना कीजिए।

- हाल ही में भारत - बांग्लादेश के राजनयिक सम्बंधों की 50 वी वर्षगांठ (1971-2021) मनाई गई।

बांग्लादेश ↔ सांस्कृतिक / ऐतिहासिक / भाषायी / नृजातीय सम्बंध ↔ भारत

नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और बांग्लादेश

(क) दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है (10.7 B$) का द्विपक्षीय व्यापार, भारत की तरफ झुका हुआ

(ख) भारत -बांग्लादेश के मध्य 4800 Km लम्बी सीमा (छिद्रित) है, जो

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अवैध प्रवासियों, रोहिंग्या शरणार्थियों व पशु तस्करी जैसे मुद्दों के कारण सीमा चुनौतियाँ है।

(ग) बांग्लादेश बहुपक्षीय संगठनों (बिम्सटेक, सार्क, हिन्द महासागर रिम एसोसिएशन) पर भारत के समर्थन हेतु आवश्यक है

(घ) क्षेत्रीय व्यापार, उत्तरी पूर्वी राज्यों में सुरक्षा, सीमापारीय आवाद आदि मुद्दों के कारण महत्वपूर्ण है।

एक्ट ईस्ट पॉलिसी और बांग्लादेश

(क) दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों (आसियान) तक पहुँच के लिए बांग्लादेश एक द्वार का काम करता है।

(ख) भारत-म्यांमार-थाईलैण्ड (IMT) राजमार्ग हेतु महत्वपूर्ण है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(ग) आसियान क्षेत्रीय मंच, पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन जैसे मंचों हेतु महत्वपूर्ण है।

(घ) कलादान -मल्टी मॉडल परिवहन परियोजना हेतु महत्वपूर्ण है।

उठाए गए कदम - (A) 'BBIN' मोटर वाहन समझौता द्वारा कनेक्टिविटी बढ़ी।

(B) रूस - भारत ने मिलकर बांग्लादेश में परमाणु बिजली संयंत्र का निर्माण कार्य

(C) अगरतला - अखौड़ा रेलवे लिंक लाइन -

(D) भारत की वैक्सीन मैत्री डिप्लोमेसी का बांग्लादेश लाभार्थी रहा

(E) 2015 में भूमि सीमा विवाद समझौता

अतः भारत ने नेबरहुड पॉलिसी व एक्ट ईस्ट पॉलिसी के रूप में बांग्लादेश को महत्वपूर्ण महत्व दिया है।